

भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन

प्रलिस के लयः

अभवऱकतकी स्वतंत्रता का अधकार, अनुच्छेद 19, राषट्रीय सुरक्षा, जनहति याचका, सर्वोच्च न्यायालय, राजदरोह ।

मेन्स के लयः

वर्ष 1951 का भारतीय संविधान का पहला संशोधन और इसके नहलतरथ ।

चर्चा में क्यों?

[सर्वोच्च न्यायालय](#) ने वर्ष 1951 में संविधान में पहले संशोधन द्वारा [भाषण और अभवऱकतकी स्वतंत्रता](#) के अधकार में कयऱ गए परवऱर्तनों को चुनौती देने वाली एक [जनहति याचका](#) की जाँच करने के लयऱ सहमतर वऱकत की है ।

- न्यायालय ने कहा कऱयह एक वऱचार-वमऱरश वाला कानूनी मुददा है और इस पर केंद्र की राय अपेक्षति है ।

याचकाकरत्ता के तरकः

- **आपत्तजनक प्रवषऱटयऱँ (Objectionable Insertions):**
 - संशोधन अधनऱयऱम की धारा 3(1) द्वारा [अनुच्छेद 19](#) के मूल खंड (2) को एक नए खंड (2) के साथ प्रतसऱथापतऱ कयऱा गया, जसऱमें दो आपत्तजनक प्रवषऱटयऱँ थीं ।
 - अनुच्छेद 19 का मूल खंड (2) अनुच्छेद 19 (1) (a) के तहत गारंटीकृत भाषण और अभवऱकतकी स्वतंत्रता पर उचतऱ प्रतबऱंधों से संबंधतऱ था ।
 - नए खंड (2) में "दो आपत्तजनक प्रवषऱटयऱँ" शामिल हैं, जो "लोक वऱवस्था के हतऱ में" और "अपराध को उकसाने के संबंध में" भी प्रतबऱंधों की अनुमतर देती हैं ।
- **राषट्रीय सुरक्षा की उपेक्षा:**
 - इस संशोधन द्वारा 'राज्य की अखंडता को नुकसान पहुँचाने के संदर्भ में अभवऱकतकी स्वतंत्रता के माधयम से [राषट्रीय सुरक्षा](#) की भी उपेक्षा की गई है, जसऱसे [कटटरपंथ](#), [आतंकवाद](#) और धार्मकऱ कटटरवाद द्वारा धरमनरऱपेक्ष लोकतांत्रकऱ गणराज्य की अवधारणा के प्रतगऱंभीर चतऱा उत्पन्न हुई है ।
- **ये दो प्रवषऱटयऱँ नमऱन धाराओं (Sections) को प्रतररऱक्षा देती हैं:**
 - 124A: [राजदरोह](#)
 - **153 A:** धरम, नसल, जन्म स्थान, नवऱस, भाषा आदऱके आधार पर वभऱनऱन समूहों के बीच शतरुता को बढावा देना और सद्भाव के प्रतकऱील कारय करना ।
 - **295A:** जानबूझकर दुरभावनापूरण कारय करना, जसऱका उददेश्य कसऱी भी वर्ग की धार्मकऱ भावनाओं या उसके धरम या धार्मकऱ वशऱवासों का अपमान करना है ।
 - **505:** असंवैधानकऱ तरऱके से भारतीय दंड संहतऱा के तहत सार्वजनकऱ वऱवस्था को नुकसान पहुँचाने वाले वकतवय देना ।
- **धारा 3 (1) (a) - 3 (2) को अपरभावी करना:**
 - इस याचका में न्यायालय से पहले संशोधन की धारा 3 (1) (a) और 3 (2) को "संसद की संशोधन शकतऱसे परे" घोषतऱ करने तथा इसे "संविधान की [आधारभूत संरचना](#) को नुकसान पहुँचाने एवं नषट करने" के आधार पर शून्य घोषतऱ करने का आग्रह कयऱा गया ।

संविधान (प्रथम संशोधन) अधनऱयऱम, 1951:

- **वषऱय:**
 - प्रथम संशोधन वर्ष 1951 में अनंतमऱ संसद द्वारा पारतऱ कयऱा गया था, जसऱके सदस्य संवैधानकऱ सभा के हसऱसे के रूप में संविधान का मसौदा तैयार करने का काम समाप्त कर चुके थे ।

- प्रथम संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 15, 19, 85, 87, 174, 176, 341, 342, 372 और 376 में संशोधन किया।
- कानून की रक्षा के लिये संपत्ति अधिग्रहण आदि की व्यवस्था।
- भूमि सुधारों और इसमें शामिल अन्य कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिये नौवीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके पश्चात अनुच्छेद 31 के बाद अनुच्छेद 31ए और 31बी जोड़े गए।

■ संशोधन का कारण:

- इन संशोधनों का तात्कालिक कारण सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के फैसलों की एक शृंखला थी, जिन्होंने सार्वजनिक सुरक्षा कानूनों, प्रेस से संबंधित कानूनों और आपराधिक प्रावधानों को खारज कर दिया था, जिन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार के साथ असंगत माना जाता था।

■ प्रभाव:

- अनुच्छेद 31 के प्रावधानों के तहत नौवीं अनुसूची में रखे गए कानूनों को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है कि उन्होंने नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है।
- अनुच्छेद 31 (ए) ने राज्य को संपत्ति के अधिग्रहण या सार्वजनिक हित में किसी भी संपत्ति या निगम के प्रबंधन के संबंध में शक्ति नहिती की है। इसका उद्देश्य ऐसे अधिग्रहणों को अनुच्छेद 14 और 19 के तहत न्यायिक समीक्षा से छूट देना था।
- नौवीं अनुसूची का व्यापक रूप से दुरुपयोग किया गया था। नौवीं अनुसूची में न्यायिक जांच से संरक्षण प्राप्त करने वाले 250 से अधिक विधान शामिल हैं।

आगे की राह

- अलग राजनीतिक संदर्भ में आयोजित होने के बावजूद प्रथम संशोधन की बहस आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि भारत में लोकतंत्र कठिन अथवा अनिश्चित समय से गुजर रहा है।
- स्टैन स्वामी की हरिसत में मौत और वपिकषी नेताओं, वकीलों तथा मानवाधिकार रक्षकों के खिलाफ पेगासस निगरानी स्याइवेयर के दुरुपयोग के बारे में हालिया खुलासे आदि इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिये संस्थागत सुरक्षा उपायों को क्यों संरक्षित एवं मजबूत किये जाने की आवश्यकता है।
- आज़ादी के 74 साल बाद प्रथम संशोधन की बहस पर फरि से विचार करना इस दृष्टि में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. भारतीय संविधान में नौवीं अनुसूची की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के काल के दौरान की गई थी? (2019)

- जवाहरलाल नेहरू
- लाल बहादुर शास्त्री
- इंदिरा गांधी
- मोरारजी देसाई

उत्तर: (a)

[स्रोत: द हिंदू](#)